



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 465 राँची, गुरुवार
27 भाद्र 1936 (श०)
18 सितम्बर, 2014 (ई०)

नगर विकास विभाग

संकल्प

31 जुलाई, 2014

विषय:-केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के कार्यान्वयन हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के स्तर से सृजित तकनीकी विशेषज्ञों के संविदा आधारित पद की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-न.प्र.नि./NULM-15/2014-3523--शहरी गरीबी के बहुआयामी होने के कारण शहरों और नगरों में विभिन्न समस्याओं का समाधान व्यापक एवं एकीकृत रूप से किए जाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में शहरी गरीबों के सामाजिक एवं व्यवसायिक असुरक्षा के निराकरण के लिए गरीबों के स्वयं सहायता समूह बनाना, बाजार की आवश्यकता के अनुसार उनका कौशल विकास करना तथा स्वरोजगार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-No.K-14011/1/2013 UPA दिनांक- 24 सितम्बर, 2013 तथा D.O.No.K-14011/1/2013 UPA दिनांक-6 फरवरी, 2014 के आलोक में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन

मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (NULM) लागू किया गया है।

2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार एवं कौशल के आधार पर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर उनकी गरीबी और असुरक्षा को दूर करना एवं शहरी फेरिवालों को उनके कार्य के लिए उपयुक्त स्थलों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी जीविका संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं शहरी आवास विहीन परिवारों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएगा।

3. योजना का कार्यान्वयन, योजना के विभिन्न घटकों के आधार पर किया जाना है। ऐसे महत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना के क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास विभाग योजना का राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी होगा। निदेशालय स्तर पर State Mission Management Unit (SMMU) एवं राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर City Mission Management Unit (CMMU) का गठन किया जाना प्रस्तावित है जिसके द्वारा योजना कार्यान्वित की जायेगी।

4. State Mission Management Unit (SMMU) एवं City Mission Management Unit (CMMU) के तहत कतिपय तकनीकी पदों का सृजन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर निर्धारित किया गया है जिसका उल्लेख योजना के दिशानिर्देश में है। दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार झारखण्ड राज्य को Big State की श्रेणी में रखा गया है जिसके तहत संविदा आधारित पदों का सृजन अपेक्षित है जिसका विवरण निम्न है:-

Sl. No	Position	No. of Experts	Max. Remuneration /Month (in Rs)
A	Technical Experts to be positioned at SMMU (State) Level:-		
1	State Mission Manager- Social Mobilisation and Institution Development (Contractual Post)	1	75000
2	State Mission Manager- Shelters and Social Infrastructure (Contractual Post)	1	75000
3	State Mission Manager- Skills and Livelihoods (Contractual Post)	1	75000
4	State Mission Manager – Financial Inclusion & Micro Enterprises (Contractual Post)	1	75000

5	State Mission Manager – HR & Capacity Building (Contractual Post)	1	75000
6	State Mission Manager – MIS & ME (Contractual Post)	1	75000
	Sub Total (A)	6	

B	Technical Experts to be positioned at CMMU (City) Level:-		
7	Manager – Social Development & Infrastructure (Contractual Post)	28	60000
8	Manager – Skills and Livelihoods (Contractual Post)	28	60000
9	Manager – Financial Inclusion & Micro Enterprises (Contractual Post)	4	60000
10	Manager – MIS & ME (Contractual Post)	4	60000
	Sub Total (B)	64	
C	Community Organiser (CO)	114	10000
	Total A+B+C	184	

5. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-8 जुलाई, 2014 की बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार उपरोक्त पदों की स्वीकृति पाँच वर्ष अथवा भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अवधि तक सीमित रहेगी।

उक्त पद पर नियुक्त कर्मियों के चयन पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पदाधिकारी/निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही नियुक्त/चयनित कर्मी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जायेगा जो नियुक्ति पत्र का अंग होगा। इससे भिन्न स्थिति एवं वित्तीय भार सृजित होने के लिए संबंधित पदाधिकारी दोषी होंगे।

6. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) का वित्त पोषण केन्द्रांश एवं राज्यांश 75:25 के अनुपात में निर्धारित है। स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के पश्चात् मानदेय का भुगतान योजना अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश एवं मैचिंग ग्रांट के रूप में स्वीकृत राज्यांश के अंतर्गत निर्धारित घटक के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से किया जाना है।

7. स्वीकृत पद पर नियुक्ति पारदर्शी तरीके से नियुक्ति समिति के द्वारा अंतर्वीक्षा के आधार पर किया जाएगा। उक्त स्वीकृत पद का मानदेय निर्धारित अधिकतम मानदेय के अंतर्गत सरकार के अनुमोदन से निर्धारित किया जाएगा।

8. उपर्युक्त उल्लेखित स्वीकृत पद की योग्यता भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगी।
9. उपर्युक्त प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।
